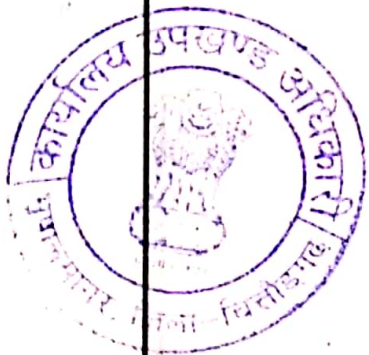


26/2/24

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार
 उपस्थित। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील
 प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि
 ग्राम नौदोली के आ० नं० 439 व 384 डिनोंक
 22.1.68 को प्रार्थी ने जगदीश पिता जयलाल से खरी
 की थी तब से प्रार्थी का कब्जा कायम है। राजस्व
 कर्मचारियों व सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से
 हाल सेटलमेन्ट आ.नं० 676 रकबा 0-15 बीघा, आ० नं०
 1184/938 रकबा 0-30 हेक्टेयर, आ.नं० 1183/937 रकबा
 0-34 हेक्टेयर हैं जो बिलानाम सरकार कर दी जो
 गलत है। प्रार्थी का मीरे पर कब्जा कायम भी है
 अतः प्रार्थी की आराजियात में राजस्व रेकॉर्ड से
 बिलानाम सरकार हटाकर प्रार्थी के नाम डुरुस्ती की
 जावे और अग्रार्थी को विरुद्ध स्थायी निवेद्याज्ञा
 जारी करावे। अग्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस
 में बताया कि उक्त जमीन बिलानाम सरकार है तथा
 प्रार्थी का इस आराजियात में कोई ठक हिस्सा निहित
 नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज करमाके।
 हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस व पत्रावली
 में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया जिसे आधा
 पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का दंतुत्तर व अपूर्ण
 प्राप्ति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं।
 अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राज
 काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य नहीं होने
 के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार
 होकर। नम्बर से रकम होकर शामिल इफ्तार के निर्णय
 आज डिनोंक 26.2.24 को खुले न्यायालय में हुआ अथा



पत्रावली कैसल शुमार
 अधिकारी, भूपालसाग
 विदोली